

- प्लेटफॉर्म श्रमकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान आय में एक नश्चिती घटक की गारंटी देने में मदद करेगा ।
 - श्रमकों की ID को ब्लॉक करने के मामलों में, ऐसी प्रथाओं की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये और श्रमकों की ID को अनश्चिती काल के लिये ब्लॉक नहीं किया जा सकता है ।
- प्लेटफॉर्म को श्रमकों की मांगों का जवाब देना चाहिये, जैसे क्पिरतलिन-देन कमीशन शुल्क कम करना या श्रमकों को अपने गैसोलीन बलियों के लिये अलग से भुगतान करने की आवश्यकता, जो ईधन की कीमतों के साथ बढ़ रहे हैं और आय अपर्याप्तता की बढ़ती चिताओं को संबोधति करना चाहिये ।
- यह अध्ययन एप-आधारति श्रमकों के लिये मज़बूत सामाजकि सुरक्षा और श्रमकों की नगिरानी के लिये प्लेटफॉर्मों द्वारा उपयोग किये जाने वाले एल्गोरदिम तथा तंत्र की नषिपक्षता पर सरकारी नगिरानी की सफिरशि करता है ।

गगि वरकर कौन हैं?

■ गगि वरकरस:

- गगि वरकर ऐसे वयक्ती होते हैं जो अस्थायी, लचीले आधार पर काम करते हैं , अक्सर कई ग्राहकों या कंपनयियों के लिये कार्य करते हैं या सेवाएँ प्रदान करते हैं ।
- वे पारंपरिक कर्मचारयियों के बजाय आम तौर पर स्वतंत्र ठेकेदार होते हैं, जसिका अर्थ है कविे कब, कहाँ और कैसे काम करते हैं, इस पर उनका अधिकि नयित्रण होता है ।

■ गगि इकोनॉमी:

- एक मुक्त बाज़ार प्रणाली जसिमें अस्थायी पद सामान्य होते हैं और संगठन अल्पकालकि कार्यो के लिये स्वतंत्र श्रमकों के साथ अनुबंध करते हैं ।



India Gig Economy Overview



Key Highlights

- 7.7 million Indians are currently engaged in gig work
- 9.9 million Indians are expected to be gig workers by 2023.
- India is projected to have 23.5 million gig workers by 2029-30

(Source: NITI Aayog)

Sector Wise Gig Hiring



2.7 Million Indian Gig Workers are engaged in **Retail Trade and Sales**



1.3 Million Indian Gig Workers are engaged in the **Transportation sector**



0.6 Million Indian Gig Workers are engaged in **Manufacturing sector**



0.6 Million Indian Gig Workers are engaged in **Finance and Insurance Services**



2.5 Million Indian Gig Workers are engaged in **E-Commerce Websites**

(Source: NITI Aayog)

Companies in the Space



Dunzo's Business grew by 94% this quarter. (27x previous growth rate)



Uber has started offering electric vehicles to customers in certain parts of the Delhi-NCR region and says it will expand its efforts over the coming months.



Swiggy Instamart expanded to delivering groceries till 3 am in the night.



गगि वरकरस को सामाजकि सुरक्षा लाभ प्रदान करना क्यों आवश्यक है?

■ आर्थकि सुरक्षा:

- 'केवल मांग-आधारति' प्रकृति के परिणामस्वरूप रोजगार की सुरक्षा की कमी होती है और आय की नरिंतरता से जुडी अनश्चितता होती है, जिससे बेरोजगारी बीमा, वकिलांगता कवरेज तथा सेवानवित्त बचत कार्यक्रमों जैसे सामाजकि सुरक्षा लाभ प्रदान करना और भी उचित हो जाता है।

■ अधिक उत्पादक कार्यबल:

- नयिकता-प्रायोजति स्वास्थय बीमा और अन्य स्वास्थय देखभाल लाभों तक पहुँच का अभावगगि वरकरस को अपरत्याशति चकित्सिा खर्चों के प्रतिसंवेदनशील बनाता है। उनके स्वास्थय एवं कल्याण को प्राथमकिता देने से एक स्वस्थ और अधिक उत्पादक कार्यबल का नरिमाण हो सकेगा।

■ अवसरों की समता:

- पारंपरकि रोजगार सुरक्षा से अपवरजन असमानता पैदा करती है, जहाँ गगि वरकरस को शोषणकारी कार्य दशाओं और अपर्याप्त मुआवजे का सामना करना पडता है। सामाजकि सुरक्षा लाभ प्रदान करने से एकसमान अवसर का नरिमाण होगा।

■ दीर्घकालकि वत्तितीय सुरक्षा:

- नयिकता-प्रायोजति सेवानवित्त योजनाओं के बनिा गगि वरकरस अपने भवषिय के लयि पर्याप्त बचत कर सकने में अक्षम हो सकते हैं। गगि वरकरस को सेवानवित्त के लयि बचत करने में सक्षम बनाने से उनके लयि भवषिय की वत्तितीय कठनाई और सार्वजनकि सहायता कार्यक्रमों पर नरिभर होने का जोखमि कम होगा।

गगि करमचारियों को सामाजकि सुरक्षा लाभ प्रदान करने की राह की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

■ वर्गीकरण और अतरिकित लचीलापन:

- स्वरोजगार और नरिभर-रोजगार के बीच की धुंधली सीमाएँ तथा कई फर्मों के लयि कार्य कर सकने या अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ सकने की स्वतंत्रता, गगि वरकरस के प्रतिकंपनी दायित्वों की सीमा नरिधारति करना कठनि बना देती है।

- गगि इकोनॉमी को इसके लचीलेपन के लयि जाना जाता है, जहाँ कामगारों को यह तय करने की अनुमति मिलती है कवि कब, कहाँ और कतिना कार्य करें।

- इस लचीलेपन को समायोजति कर सकने और गगि वरकरस की वविधि आवश्यकताओं को पूरा कर सकने वाले सामाजकि सुरक्षा लाभों को डिजाइन करना एक जटलि कार्य है।

■ वत्तिपोषण और लागत वतिरण:

- पारंपरकि सामाजकि सुरक्षा प्रणालियाँ नयिकता और करमचारी के योगदान पर नरिभर करती हैं, जहाँ नयिकता आमतौर पर लागत के एक उल्लेखनीय भाग का वहन करते हैं।

- गगि इकोनॉमी, जहाँ करमचारी प्रायः स्व-नयोजति होते हैं, के लयि एक उपयुक्त वत्तिपोषण तंत्र की पहचान करना जटलि हो जाता है।

■ समन्वय एवं डेटा साझाकरण:

- वभिनिन सामाजकि सुरक्षा कार्यक्रमों के लयि गगि वरकरस के आय अर्जन, योगदान एवं पात्रता का सटीक आकलन करने के लयि गगि प्लेटफॉर्म, सरकारी एजेंसियों तथा वत्तितीय संस्थानों के बीच कुशल डेटा साझाकरण और समन्वयन आवश्यक है।

- लेकिन गगि वरकरस प्रायः कई प्लेटफॉर्म या क्लाइट्स के लयि कार्य करते हैं, जिससे इस संदर्भ में समन्वय करना और उचित कवरेज सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

■ शकिषा और जागरूकता:

- कई गगि वरकरस सामाजकि सुरक्षा लाभों के संबंध में अपने अधिकारों और पात्रता से अनभजिज्ञ भी हो सकते हैं।

- इनकी जागरूकता बढ़ाना और सामाजकि सुरक्षा, पात्रता मानदंड एवं आवेदन प्रक्रिया के महत्त्व के बारे में शकिषति करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

गगि वरकरस की सामाजकि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लयि क्या उपाय कयिा जा सकता है?

■ सामाजकि सुरक्षा पर संहति कार्यान्वयन, 2020:

- हालाँकि सामाजकि सुरक्षा संहति, 2020 में गगि श्रमिकों के लयि प्रावधान शामिल हैं, नयिम अभी तक राज्यों द्वारा तैयार नहीं कयि गए हैं और साथ ही बोर्ड की स्थापना के संदर्भ में बहुत कुछ नहीं हुआ है। अतः सरकार को इन पर शीघ्रता से कार्य करना चाहयि।

■ अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों को अपनाना:

- यूके ने गगि श्रमिकों को "श्रमकि" के रूप में वर्गीकृत करके एक मॉडल स्थापति कयिा है, जो करमचारियों और स्व-रोजगार के बीच की एक श्रेणी है।

- इससे उन्हें न्यूनतम वेतन, सवैतनकि छुट्टियाँ, सेवानवित्त लाभ योजनाएँ और स्वास्थय बीमा प्राप्त होता है।

- इसी प्रकार इंडोनेशिया में वे दुर्घटना बीमा, स्वास्थय बीमा एवं मृत्यु बीमा के होते हैं।

■ नयिकता उत्तरदायित्वों का वसितार:

- गगि श्रमिकों हेतु मज़बूत समर्थन उन गगि कंपनियों से आना चाहयि जो स्वयं इस जटलि एवं कम लागत वाली कार्य व्यवस्था से लाभानवति होती हैं।

- गगि श्रमिकों को स्व-रोजगार अथवा स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में वर्गीकृत करने की प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता है।

- कंपनियों को नयिमति करमचारी के समान लाभ दयिा जाना चाहयि।

■ **सरकारी समर्थन:**

- सरकार को शिक्षा, वित्तीय सलाहकार, कानूनी, चिकित्सा अथवा ग्राहक प्रबंधन क्षेत्रों जैसे उच्च कौशल वाले गिग कार्यों में व्यवस्थित रूप से नरियात बढ़ाने में नविश करना चाहिये; भारतीय गिग श्रमिकों हेतु वैश्विक बाजारों तक पहुँच को आसान बनाकर।
- साथ ही सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की ज़िम्मेदारी साझा करने हेतु नषिपक्ष एवं पारदर्शी तंत्र स्थापित करने के लिये सरकारों, गिग प्लेटफॉर्मों एवं श्रमिक संगठनों के बीच सहयोग की आवश्यकता होगी।

गिग श्रमिकों से संबंधित सरकार की पहल:

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** में 'गिग इकॉनमी' पर एक अलग खंड शामिल है और साथ ही गिग नियोक्ताओं पर सरकार के नेतृत्व वाले बोर्ड द्वारा प्रबंधित सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान करने का दायित्व भी दिया गया है।
- **वेतन संहिता, 2019** गिग श्रमिकों सहित संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन एवं आधारभूत वेतन प्रदान करता है।

नषिकर्ष

एप-आधारित श्रमिकों की कार्य स्थितियों, वित्तीय सुरक्षा एवं समग्र कल्याण में सुधार हेतु व्यापक उपायों की आवश्यकता है, उनके अधिकारों तथा सुरक्षा की वकालत करते हुए गिग अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता दी जाए।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?]:

प्रश्न. भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण की प्रक्रिया में 'गिग इकॉनमी' की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (2021)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/challenges-faced-by-the-gig-workers>